भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1956

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहन

†1956. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम प्रदूषण और कम परिचालन लागत के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है,और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों ने विशेषकर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों के न होने पर चिंता व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने नगरों, शहरों और राजमार्गों के सभी प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन सेवा चार्जिंग पॉइंट प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए हैं तथा क्या असम में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों की तुलना में कम परिचालन लागत और शून्य उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। वीएएचएएन के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ वित्त वर्ष 2019-20 में 0.71% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 8.26% हो गई है।

(ख) से (घ) निजी क्षेत्र विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के 17 सितंबर, 2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के अंतर्गत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 'फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक

व्हीकल्स' (एफएएमई-II) और 'प्रधानमंत्री की इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट' (पीएम ई-ड्राइव) योजनाओं का संचालन कर रही है। एफएएमई-II योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए 912.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एमएचआई ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित, पर्याप्त संख्या में ईवीपीसीएस की तैनाती के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

वाहन के आंकड़ों के अनुसार, सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या (26-07-2026 तक) 1,00,23,396 है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 31.03.2026 तक देश में 52,718 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं।

(ड़) "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" एक कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) नामक तीन तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफएएमई-II योजना के तहत असम के लिए कुल 117 ईवीपीसीएस स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 88 ईवीपीसीएस 01.07.2026 तक परिचालन में हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के माध्यम से मार्गस्थ सुविधाओं के विकास की परिकल्पना कर रहा है। इन सुविधाओं का उद्देश्य सड़क प्रयोक्ताओं और ट्रक चालकों को भोजनालय, शौचालय, पेयजल, पार्किंग, ईंधन स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, अल्पकालिक आवास आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करना है। वर्तमान में, असम राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा से लैस 3 मार्गस्थ सुविधाएं (डब्ल्यूएसए) स्थल क्रियाशील हैं।

इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत असम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****